

मुकदमों का विवरण

वजीर खान

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 1922-1923) अगस्त 02,2023

[जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:परिस्थितिजनक साक्ष्य पर निर्भर एक मामले में, जहां अपीलार्थी पर यू/एस. एस. के तहत मुकदमा चलाया गया था। 302 और 201 भारतीय दण्ड संहिता सी. अपनी पत्नी की हत्या के लिए, और उसने घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया और इसके अलावा, अपनी पत्नी द्वारा प्राप्त चोटों के संबंध में उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण गलत पाया गया, क्या उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलटने में उचित ठहराया गया था।

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 और 201-उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को उलटना-स्वामित्व:

आयोजित किया गया:जब अपीलार्थी का ध्यान उन दोषपूर्ण परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया गया, जिन्होंने उसे अपराध में शामिल किया, तो वह उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा या गलत उत्तर दिया-उसी को परिस्थितियों की एक श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक लापता कड़ी प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है-जहां एक आरोपी पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है और अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए प्रमुख साक्ष्य देने में सफल हो जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, कि अपराध करने से कुछ समय पहले उन्हें एक साथ देखा गया था या अपराध उस आवास में हुआ था जहां पति भी सामान्य रूप से रहता था, यह लगातार माना जाता है कि यदि आरोपी संबंधित समय पर घर पर अपनी उपस्थिति पर विवाद नहीं करता है और कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि पत्नी को कैसे चोटें आईं या एक स्पष्टीकरण दिया गया जो पाया जाता है।

अभियुक्त का अपराध, यदि न्यायालय द्वारा परिस्थितिजनक साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है-तथ्यों पर, दोषी अपीलार्थी-उच्च न्यायालय द्वारा उसे बरी करने के फैसले को पलट दिया जाता है।[पैरा 24,25 और 29]

परिस्थितिजन्य साक्ष्य-अभियुक्त और अभियुक्त के सामने कोई स्पष्टीकरण नहीं देना या गलत स्पष्टीकरण देना-परिस्थितियों की श्रृंखला में अतिरिक्त कड़ी:

आयोजित किया गया:परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर एक मामले में जहां कोई चश्मदीद गवाह उपलब्ध नहीं है, सिद्धांत का पालन किया जाता है कि जब अभियुक्त के सामने एक आपत्तिजनक परिस्थिति रखी जाती है और उक्त अभियुक्त या तो कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है जो असत्य पाया जाता है, तो वह इसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है।[पैरा 23]

साक्ष्य-साक्ष्य का नेतृत्व करने का अभियोजन पक्ष का कर्तव्य-इसकी प्रकृति:

आयोजित किया गया:कानून अभियोजन पक्ष को ऐसे चरित्र के साक्ष्य का नेतृत्व करने का कर्तव्य नहीं देता है, जिसका नेतृत्व करना लगभग असंभव है, या किसी भी तरह से, अत्यंत कठिन पंथ का नेतृत्व किया जाना-अभियोजन पक्ष का कर्तव्य ऐसे साक्ष्य का नेतृत्व करना है, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करने में सक्षम हो।[पैरा 29]

**साक्ष्य अधिनियम, 1872 -s.106:**

आयोजित किया गया:अभियोजन पक्ष एस का सहारा नहीं ले सकता है।**106** कोई भी मूलभूत तथ्य रखे बिना अधिनियम, **1872** का।[पैरा **17**]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर और अन्य। (2000) 8 एससीसी 382: [2000] 2 पूरकाएससीआर 712; धर्म दास वाधवानी बनाम उत्तर राज्य

प्रदेश आकाशवाणी 1975 एससी 241:[1974] 3 एससीआर 607; निका राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एआईआर 1972 एससी 2077:[1973] 1 एस. सी. आर. 428; गणेश लाल बनाम राज्य

राजस्थान (2002) 1 एससीसी 73; यू. पी. राज्य बनामडॉ. रवींद्र प्रकाश मित्तल, आकाशवाणी

1992 एससी 2045:[1992] 2 एससीआर 815-पर निर्भर था।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2017 की आपराधिक अपील संख्या 1922-1923।

वजीर खान बनाम उत्तराखंड राज्य

2011 के जी. ए. सं. 10 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.07.2017 और 09.08.2017 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

डॉ. राजेश पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, चतुरानन चौबे, अभिषेक पांडे, सुश्री मृदुला रे भारद्वाज, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डॉ. अभिषेक अत्रे, सुश्री रचना गांधी, सुश्री अंबिका अत्रे, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. ये अपीलें अपीलार्थी/दोषी-वजीर खान के कहने पर की जाती हैं और 2011 की सरकारी अपील संख्या 10 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (ओं) और आदेश (ओं) दिनांकित (आई. डी. 2) (दोषसिद्धि) और (आई. डी. 1) (सजा) के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-उत्तराखंड राज्य के नेतृत्व में अपील को अनुमति दी और इस तरह निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश को उलट दिया। 2. मृतक-बुशरा अपीलार्थी/दोषी-वजीर खान की पत्नी थी। अपीलार्थी/दोषी-वजीर खान पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आई. पी. सी".) की धारा 305 और 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2007 के सत्र परीक्षण संख्या 158 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड की अदालत में मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी/दोषी-वजीर खान ने अपनी पत्नी-बुशरा की हत्या चाकू से उसके पूरे शरीर पर घाव फोड़कर की थी।
3. ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मदाहयात ने 23.07.2007 पर टेलीफोन पर पुलिस को सूचित किया कि अपीलार्थी की मृतक/पत्नी की उसके घर में हत्या कर दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना 22.01.2007 और 23.01.2007 की दरम्यानी रात के दौरान हुई थी। शव का पंचनामामशव का पंचनामामृशव का पंचनामातशव का पंचनामाकशव का पंचनामा शव का पंचनामाकशव का पंचनामोशव का पंचनामा शव का पंचनामाशशव का पंचनामावशव का पंचनामा शव का पंचनामाकशव का पंचनामाशव का पंचनामा शव का पंचनामापशव का पंचनामांशव का पंचनामाचशव का पंचनामानशव का पंचनामाशव का पंचनामामशव का पंचनामाशव का पंचनामा शव का पंचनामातशव का पंचनामौशव का पंचनामायशव का पंचनामाशव का पंचनामारशव का पंचनामा शव का पंचनामाकशव का पंचनामिशव का पंचनामायशव का पंचनामाशव का पंचनामा शव का पंचनामागशव का पंचनामायशव का पंचनामाशव का पंचनामा शव का पंचनामाथशव का पंचनामाशव का

पंचनामा।शव का पंचनामाइसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिकॉर्ड पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरे शरीर पर 17 घाव थे।अपीलार्थी-वजीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया।अनुसंधान पूरी होने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया।अपीलार्थी-वजीर खान ने आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

42

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

4. अभियोजन पक्ष ने कम से कम 10 गवाहों से पूछताछ की और अपने मामले के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य का भी नेतृत्व किया।अपीलार्थी के बयान में-वजीर खान ने Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज किया, उन्होंने कहा कि घटना की तारीख को उनकी पत्नी को लुटेरों ने मार डाला था।अपने आगे के बयान में, उन्होंने यह भी कहा कि लुटेरों ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन उन्हें भी लुटेरों के हाथों दम घुटने से चोटें आईं।

5. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने पर निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और तदनुसार अपीलार्थी-वजीर खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

6. प्रत्यर्थी-राज्य, निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में गया।उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले और आदेश को विकृत पाया, और तदनुसार बरी करने के फैसले को उलट दिया और अपीलार्थी-वजीर खान को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया।

7. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता-वजीर खान वर्तमान अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष हैं।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजेश पांडे ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के सुविचारित फैसले को बाधित करने में गंभीर गलती की है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को बरी करने के फैसले को केवल इस संतुष्टि पर पलटने में न्यायसंगत ठहराया जाएगा कि निचली अदालत का फैसला विकृत है या कोई सबूत नहीं है।वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि पूरा मामला परिस्थितिजनक साक्ष्य पर निर्भर करता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मामले के रिकॉर्ड में कोई आपत्तिजनक परिस्थितियाँ सामने नहीं आ रही हैं, ताकि अपीलार्थी को अपराध से जोड़ा जा सके।वह प्रस्तुत करेगा कि सिर्फ इसलिए कि मृतक अपीलार्थी की पत्नी थी और घटना उसके घर में हुई थी, अपीलार्थी को हत्या के अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

9. उन्होंने कहा कि जिन अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की गई है, उनमें से किसी को भी विश्वसनीय गवाह नहीं कहा जा सकता है।

10. उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए हथियार, कपड़े आदि को अभी तक रासायनिक विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) नहीं भेजा गया है। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड पर कोई सीरोलॉजिकल परीक्षण रिपोर्ट नहीं है।

43

वजीर खान बनाम उत्तरखंड राज्य

11. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रार्थना करता है कि वर्तमान अपीलों में योग्यता होने के कारण इसकी अनुमति दी जा सकती है और अपीलार्थी-वजीर खान को सभी आरोपों से बरी किया जा सकता है।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक एटेरी ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया और कहा कि निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश को उलटने में उच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी भी त्रुटि के बारे में बात करने के लिए कोई त्रुटि नहीं है। वह प्रस्तुत करेगा कि आरोपी ने घटना के समय घर में अपनी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह अपीलार्थी/अभियुक्त को समझाना है कि घटना की तारीख को वास्तव में क्या हुआ था। वह प्रस्तुत करेगा कि यदि घर की चार दीवारों के भीतर कुछ होता है, तो केवल अपीलार्थी/अभियुक्त ही समझा सकता है, क्योंकि इसे उसके विशेष ज्ञान के भीतर कुछ कहा जा सकता है।

13. उन्होंने आगे बताया कि अपराध का हथियार यानी खून से सना चाकू भी अपीलार्थी/आरोपी के कहने पर घर से ही बरामद किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "अधिनियम, 1872") की धारा 106 का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि जहां कुछ तथ्य किसी भी व्यक्ति के ज्ञान में हैं, उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। यदि अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव झूठा पाया जाता है तो यह दोषी के खिलाफ जाने वाली एक अतिरिक्त परिस्थिति होगी।

14. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, वह प्रार्थना करता है कि वर्तमान अपीलों में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, उन्हें खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण:-

15. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है।

16. हम मामले के अभिलेख से उत्पन्न निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं:-

1. मृतक अपीलार्थी-वजीर खान की पत्नी थी।ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी-वजीर खान के मृतक के साथ वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण थे।

44

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

2. अपीलार्थी-वजीर खान ने घटना के समय घर में अपनी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया है।हालाँकि, उसने बचाव किया है कि लुटेरे उसके घर में घुस गए और उसकी पत्नी की हत्या कर दी।उन्होंने यह भी कहा कि जब उनकी पत्नी पर लुटेरों द्वारा हमला किया जा रहा था, तब उन्हें भी दम घुटने से चोटें आई थीं।3. उपरोक्त संदर्भ में, हम केवल यह कह सकते हैं कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अपीलार्थी-वजीर खान को कोई चोट लगी थी।अपीलार्थी-वजीर खान द्वारा प्रस्तुत पूरे बचाव को झूठा बचाव कहा जा सकता है।

4. मृतक के शरीर पर 17 घाव थे।अगले दिन, जब पुलिस अपीलार्थी-वजीर खान को घटना स्थल पर ले आई, तो उसने उस जगह की ओर इशारा किया जहाँ चाकू छोड़ा गया था।घटना स्थल से ही बंदूक बरामद की गई थी।

17. यहाँ एक मामला है, जिसमें कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अधिनियम, 1872 की धारा 106 को लागू करने के उद्देश्य से कानूनी नींव रखी थी।निस्संदेह, अपीलार्थी-वजीर खान के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।यदि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो अपीलार्थी-वजीर खान को बरी कर दिया जाना चाहिए।यह स्थापित विधि है कि अभियोजन पक्ष कोई भी मूलभूत तथ्य रखे बिना अधिनियम, 1872 की धारा 106 का सहारा नहीं ले सकता है।हालाँकि, मामले में, हम आश्चर्य हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए मूलभूत तथ्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 को लागू करने के लिए पर्याप्त हैं।

18. दूसरी ओर, अपीलकर्ता-वजीर खान का डकैती और उसकी पत्नी पर हमला करने वाले लुटेरों का बचाव पूरी तरह से गलत है।

19. सबूत के बोझ का सवाल, जहां कुछ तथ्य अभियुक्त की व्यक्तिगत जानकारी में हैं, इस अदालत द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर और अन्य के मामले में जांचा गया था।, (2000) 8 एस. सी. सी. 382 में सूचित किया गया।

20. पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर) में, हमलावरों ने मृतक महेश को उस घर से जबरन घसीटा जहां वह आरोपी के डर से शरण ले रहा था, और लगभग 2 बजे उसे ले गए:30 रात में।अगले दिन सुबह उसका क्षत-विक्षत शव अस्पताल में पड़ा मिला।निचली अदालत ने अभियुक्तों को

भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ धारा 364 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त ने पहले से ही 45

वजीर खान बनाम उत्तरखंड राज्य

उच्च न्यायालय और राज्य के समक्ष उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील ने भी हत्या के आरोप में अभियुक्तों को बरी किए जाने को चुनौती देते हुए एक अपील का नेतृत्व किया। अभियुक्त ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि उनके द्वारा महेश के अपहरण के बाद उसके साथ क्या हुआ था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने परिस्थितिजनक साक्ष्य पर कानून का उल्लेख करने के बाद कहा था कि मृतक को आखिरी बार अभियुक्त व्यक्तियों के साथ देखे जाने और अस्पताल में शव की खोज के बाद साक्ष्य की श्रृंखला में एक संबंध नहीं है और यह निष्कर्ष निकाला था कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के आरोप को किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा था।

21. इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों पर ध्यान दिया और रिपोर्ट के पैराग्राफ 31 से 34 में निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया:

“31. यह मूल नियम कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है, को एक जीवाश्म सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जैसे कि यह बुद्धिमान तर्क की किसी भी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता है। अनुमान का सिद्धांत उपरोक्त नियम के लिए विदेशी नहीं है, न ही यह नियम के स्वभाव को प्रभावित करेगा। दूसरी ओर, यदि अभियोजन पक्ष के सबूत के बोझ से संबंधित पारंपरिक नियम को पांडित्यपूर्ण कवरेज में लपेटने की अनुमति दी जाती है, तो गंभीर अपराधों में अपराधी प्रमुख लाभार्थी होंगे और इस तरह से पीड़ित व्यक्ति होगा।

32. इस मामले में, जब अभियोजन पक्ष पूर्व-वर्णित परिस्थितियों को स्थापित करने में सफल रहा, तो अदालत को कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक पाठ्यक्रम है जिस पर अदालत इस तरह की स्थितियों में भरोसा करती है।

33. तथ्य का अनुमान कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में एक अनुमान है, जब तक कि इस तरह के अनुमान की सच्चाई को गलत नहीं माना जाता है। तथ्य का अनुमान कानून का एक नियम है कि अन्यथा संदिग्ध तथ्य का अनुमान कुछ अन्य सिद्ध तथ्यों से लगाया जा सकता है। जब साबित तथ्यों के अन्य समूह से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, तो अदालत तर्क की एक प्रक्रिया का प्रयोग करती है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती है। उपरोक्त सिद्धांत को भारत में विधायी मान्यता प्राप्त हुई है जब धारा 114 को साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया है। यह 46 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

अदालत को किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाने का अधिकार देता है जो उसे लगता है कि होने की संभावना है। उस प्रक्रिया में न्यायालय मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण आदि के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखेगा।

34. जब अदालत की संतुष्टि के लिए यह साबित हो जाता है कि आरोपी ने महेश का अपहरण कर लिया था और वे उसे उस क्षेत्र से बाहर ले गए, तो केवल आरोपी को ही पता था कि उसके साथ क्या हुआ जब तक कि वह उनके साथ नहीं था। यदि अपहरण के बाद थोड़े समय के भीतर उसकी हत्या पाई जाती है तो अनुमत तर्क प्रक्रिया अदालत को यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगी कि आरोपी ने उसकी हत्या की है। इस तरह के निष्कर्ष को बाधित किया जा सकता है अगर आरोपी अदालत को बताए कि महेश के साथ और क्या हुआ जब तक कि वह उनकी हिरासत में नहीं था।”

22. उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत बरी होने के आदेश को उलट दिया, और अभियुक्तों को उक्त प्रावधान के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

23. परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित मामले में जहां कोई चश्मदीद गवाह उपलब्ध नहीं है, कानून का एक और सिद्धांत है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि जब एक दोषपूर्ण परिस्थिति को अभियुक्त के सामने रखा जाता है और उक्त अभियुक्त या तो कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या एक स्पष्टीकरण देता है जो असत्य पाया जाता है, तो वह इसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है। यह विचार इस न्यायालय के निर्णयों के एक समूह में लिया गया है, जिनके नाम हैं, निका राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2077, गणेश लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2002) 1 एस. सी. सी. 73, और यू. पी. राज्य बनाम हिमाचल प्रदेश। डॉ. रवींद्र प्रकाश मित्तल, ए. आई. आर 1992 एस. सी. 2045। 24. जब दोषी अपीलार्थी-वजीर खान का ध्यान उन दोषपूर्ण परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया गया, जिन्होंने उसे अपराध में शामिल किया, तो वह उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा या गलत जवाब दिया। इसे परिस्थितियों की एक श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक लापता कड़ी प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है।

25. जहाँ एक अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है और अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले की तरह यह दिखाने के लिए प्रमुख साक्ष्य देने में सफल हो जाता है कि अपराध करने से कुछ समय पहले उन्हें देखा गया था 47

यदि अभियुक्त प्रासंगिक समय पर घर पर अपनी उपस्थिति पर विवाद नहीं करता है और कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि पत्नी को चोट कैसे लगी या कोई स्पष्टीकरण जो गलत पाया जाता है, तो यह एक मजबूत परिस्थिति है जो इंगित करती है कि वह अपराध करने के लिए जिम्मेदार है।

26. उचित संदेह से परे सबूत के बिंदु पर अभियुक्त की ओर से बहुत तर्क दिया गया था। अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, मामला ऐसा है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार है।

27. उपरोक्त संदर्भ में, हम धर्म दास वाधवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 241 के मामले में पैरा 13 में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत कर सकते हैं:

“13. तब सवाल यह है कि क्या वर्तमान मामले में अपराध इंगित करने वाली परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा है कि अदालत यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि आरोपी दोषी हो सकता है, बल्कि वह दोषी होना चाहिए। हमें यहाँ 'अवश्य' की इस मानसिक भावना के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इसे हर विपरीत संभावना के बहिष्कार के साथ भ्रमित किया जा सके। हमने एस. एस. बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2622 में समझाया है कि उचित संदेह से परे सबूत को बरी करने के सिद्धांत में विकृत नहीं किया जा सकता है जब कोई नाजुक या दूरस्थ संदेह एक कमजोर दिमाग को पीछे छोड़ देता है। इन टिप्पणियों को ऐसी संभावनाओं पर बार-बार बरी किए जाने से प्रमाणित किया जाता है जिन्हें उच्च न्यायालयों द्वारा कभी-कभी दरकिनार नहीं किया जाता है जिससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता कमजोर होती है। उचित संदेह के लाभ के नियम का अर्थ यह नहीं है कि एक कमजोर विलो हिचकिचाहट के हर झोंके पर झुकता है। न्यायाधीश कठोर सामग्री से बने होते हैं और उन्हें साक्ष्य, परिस्थितिजन्य या प्रत्यक्ष के कारण वैध निष्कर्षों के बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। साथ ही, जैसा कि इस न्यायालय ने काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2773 में कहा है कि यदि अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई उचित संदेह उत्पन्न होता है, तो उसका लाभ उससे रोका नहीं जा सकता है।”

(बल दिया गया)

48

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

28. अदालतों के समक्ष अक्सर ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पति, तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों और चरित्र के संबंध में संदेह के कारण, पत्नी की हत्या करने की हद तक चले गए हैं। ये अपराध आम तौर पर घर के अंदर पूरी तरह से गोपनीयता में किए जाते हैं और अभियोजन पक्ष के

लिए सबूत पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है।वर्तमान मामले की तरह, परिवार का कोई भी सदस्य, भले ही वह अपराध का गवाह हो, परिवार के किसी अन्य सदस्य के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आएगा।

29. यदि किसी घर की चार दीवारों के अंदर और ऐसी परिस्थितियों में जहां हमलावरों को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में साजिश रचने और अपराध करने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करना बेहद मुश्किल होगा, अगर अदालतों द्वारा परिस्थितिजनक साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है।2007 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पृष्ठ 20 में रिपोर्ट किए गए त्रिमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता नहीं करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है।यह न्यायालय यह अवलोकन करने के लिए आगे बढ़ा कि एक न्यायाधीश यह देखने के लिए भी अध्यक्षता करता है कि एक दोषी व्यक्ति बच न जाए।दोनों सार्वजनिक कर्तव्य हैं।कानून अभियोजन पक्ष को ऐसे चरित्र के साक्ष्य का नेतृत्व करने का कर्तव्य नहीं देता है, जिसका नेतृत्व करना लगभग असंभव है, या किसी भी तरह से, अत्यंत कठिन पंथ का नेतृत्व किया जाना है।अभियोजन पक्ष का कर्तव्य इस तरह के साक्ष्य का नेतृत्व करना है, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करने में सक्षम है।

30. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

31. तदनुसार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

32. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

बिभूति भूषण बोस